

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून: दिनांक : 16 अगस्त, 2016

विषय:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-503/2013 “बाजपुर में 01 स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा” की पूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-605/बाज०स्ट०पत्रा०/2012-13/द०दून, दिनांक 10 अगस्त, 2016, शासनादेश संख्या-287/VI-2/2015-22(12)/2013, दिनांक 28 मार्च, 2015, शासनादेश संख्या-489/VI-2/2015-22(12)/2013-टी०सी०-III, दिनांक 03 सितम्बर, 2015 एवं शासनादेश संख्या-122/VI/2015-22(12)/2013-टी०सी०-III, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-503/2013 “बाजपुर में 01 स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा” हेतु प्रस्तुत आगणन ₹341.80 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा संस्तुत आगणन ₹ 336.99 लाख (सिविल कार्यों हेतु ₹ 284.02 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹ 52.97 लाख) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रथम किश्त के रूप में ₹ 100.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2015-16 में द्वितीय किश्त के रूप में ₹ 14.20 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में तृतीय किश्त के रूप में ₹ 25.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त अवशेष बची धनराशि ₹ 197.79 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष चतुर्थ किश्त के रूप में ₹ 33.33 लाख (₹ तैतीस लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2— प्रस्तावित सभी कार्यों को एक प्राजेक्ट के रूप में करते हुये प्रथम फेज के कार्यों यथा आदि के कार्यों तथा अवशेष कार्यों को प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष 2015-16 की समाप्ति तक पूर्ण कर लिया जाय, ताकि Cost over & run न हो। किसी भी स्थिति में पुनः पुनरीक्षित आगणन तथा नये कार्यों को प्रस्तावित नहीं किया जायेगा। आगामी स्वीकृति मांगे जाने के समय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवश्य अवगत कराया जाय।

3— कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008 दिनांक-15.12.2008, शासनादेश संख्या-414/XXVII(7)/2007, दिनांक-23.10.2008 एवं शासनादेश संख्या-594/XXVII(7)/2010 दिनांक-09.06.2010 के अनुसार MOU हस्ताक्षरित कर समय सारिणी के अनुरूप उक्तानुसार समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायें। निर्माण कार्य का गहन अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय।

4— पानी की कमी को दूर करने के लिए विकल्प के रूप में चैकडैम टैक्नीकल फिजीबिलिटी का परीक्षण वन विभाग /सिंचाई विभाग से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5— कार्य करने से पूर्व मदवारदर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों के आधार पर जो दरें शेड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृति नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता / सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराया जाय।

6— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7— कार्य करने से पूर्व से समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

8— कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली—भाति निरीक्षण अवश्यक करा लिया जाय, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

9— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—2047 /XIV—219(2006) दिनांक 30. 05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

10— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्यों से इतर कार्यों/उपकरणों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली—2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड —05 भाग—1 (लेखा नियम), आय—व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों से कड़ाई से पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11— निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपर्युक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय। कार्य के गुणवत्ता परीक्षण के संबंध में नियोजन विभाग से समन्वय का तदनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त के सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सेन्ट्रेज से वहन किया जायेगा।

12— स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2015 तक उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण—पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा तथा यदि कोई बचत होती है, तो उसे राजकोष में समर्पित कर दिया जायेगा। निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपर्युक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण के संबंध में नियोजन विभाग से समन्वय का तदनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त के सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सेन्ट्रेज से वाहन किया जायेगा।

13— उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016—17 के अनुदान संख्या—11 के लेखाशीर्षक—4202—शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—03—खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम—102—खेलकूद स्टेडियम—05—स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य)—24—वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक: अलाटमेंट आई०डी० संख्या—५१६०४१०४७७, दिनांक : १६ अगस्त, २०१६

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

पुष्टांकन संख्या—६४७/VI/2016—२२(१२)/२०१३—टी०सी०—III, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—३, उत्तराखण्ड शासन।
7. परियोजना प्रबन्धक (कार्य०), उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड, इकाई कार्यालय, 85 हीरानगर (ब्लौसिंग्स), हल्द्वानी, नैनीताल—263139
8. जिला कीड़ाधिकारी, उधमसिंह नगर।
9. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।